Press note

FSSAI issues two draft notifications aimed at protecting consumers

FSSAI has notified two important draft regulations, both aimed at protecting the interests of consumers. While the Draft Food Safety and Standards (Organic Foods) Regulations, 2017, is meant to ensure the safety and authenticity of all foods labelled ''organic', the draft Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2017, is intended to curb adulteration of edible oil with cheaper oils .

Both have been put up on the FSSAI website, inviting public/stakeholder comments within 30 days.

Regulation on organic foods

Organic food products are either those grown under a system of agriculture without the use of chemical fertilizers and pesticides or made from organically produced raw materials. Currently, a number of food products are being marketed as organic'', but in the absence of a regulatory framework to ensure their safety and organic status, consumers have no way of checking their authenticity. The draft regulation on organic food is aimed at overcoming this problem and ensuring that what is sold as organic food is really organic.

As per the draft FSS (Organic Foods) Regulations, any food offered for sale as 'organic food'' should comply with the provisions laid down under either the National Programme for Organic Production (NPOP) administered by the Government of India or the Participatory Guarantee System for India (PGS-India) operated by the ministry of Agriculture and Farmers' Welfare or any other system or standards that may be notified by the Food Authority from time to time.

The draft regulation also mandates that such foods not only convey full and accurate information on the organic status of the product, but also carry a certification mark or a quality assurance mark given by any of the notified certification bodies. .

The draft however exempts organic food marketed through direct sale by the original producer or producer organisation to the end consumer from verification compliance, but this exemption does not apply to processed organic products.

Curbing misleading claims and adulteration of edible oils with cheaper oils

The draft FSS (Food Product Standards and Food Additives) Amendment Regulation, 2017, incorporates in the standards for edible oils, their fatty acid compositions , thereby paving the way for determination of the authenticity of the edible oils.

Since the fatty acid composition is different for each edible oil, this amendment will go a long way in exposing and curbing two malpractices in the edible oil sector: adulteration of expensive oils with cheaper oils and (b) misleading label claims on the composition of blended oils. In other words, the amendment will help in determining the authenticity of the oil in cases of adulteration and quantification of proportion of oils used in blended oils.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, सोमवार, जून 19, 2017/ज्येष्ठ 29, 1939
No. 243] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 19, 2017/JYAISTHA 29, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2017

फा. सं. सीपीबी/03/स्टैंडर्ड्स/एफएसएसएआई/2016.- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई), केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 22 की उप-धारा 3 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार प्रकाशित किया जाता हैं जिनके उससे प्रभावित होने कि संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से, जिसको उस राजपत्र की प्रतिया, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित कि जाती है जनता को उपलब्ध करा दी जाती है तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को या regulation@fssai.gov.in के ई-मेल पते पर भेजे जा सकते है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप विनियम

अध्याय 1

साधारण

1. **संक्षित नाम एवं प्रारंभ –** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) विनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - (1) इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रत्यायन निकाय" से खाद्य प्राधिकरण द्वारा इस रूप में मान्यता-प्राप्त या प्रमाणन संस्थाओं के प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अधीन मान्यता-प्राप्त कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "प्रत्यायित प्रमाणन निकाय" से किसी प्रत्यायन संस्था द्वारा जैविक उत्पादों के प्रमाणन और उसकी ओर से खाद्य कारोबारियों को प्रमाणन मुहर के उपयोग का अधिकार देने वाला सम्यक रूप से प्रत्यायित कोई संगठन अभिप्रेत है ;

(घ) "दावा" से कोई ऐसा प्रतिवेदन अभिप्रेत है, जिसमें कथन या सुझाव हो या जिससे यह अभिप्रेत हो कि किसी खाद्य में उसकी उत्पत्ति, पौषणिक गुणधर्म, प्रकृति, प्रसंस्करण और सम्मिश्रण के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट गुण है;

(ङ) "खाद्य प्राधिकरण" से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम" से भारत सरकार का ऐसा कार्यक्रम अभिप्रेत है ,जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अधीन अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानकों के कार्यान्वयन के लिए महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा यथा अधिसूचित तृतीय पक्ष प्रमाणन नियंत्रण प्रणाली वाली संस्थागत प्रणाली का उपबंध करता है;

(छ) "जैव उत्पादन मानक" से खाद्य प्राधिकरण या राष्ट्रीय जैव उत्पादन मानक या भारत के लिए प्रत्याभूति प्रणाली द्वारा मान्यता प्राप्त मानक अभिप्रेत है, जिनका अनुपालन जैव खाद्य उत्पादों की खेती या कटाई या उत्पादन या भंडारण या प्रसंस्करण या व्यापार और विनिवेशों में किया जाना है;

(ज) "जैव कृषि" से रसायनों, उर्वरकों, पेस्टीसाइडों जैसी संश्लेषित बाहरी सामग्रियों, संश्लेषित हारमोनों या जीन-परिवर्तित जीवाणुओं के उपयोग के बिना कृषि उत्पादन का परस्थितिक तंत्र तैयार करने के लिए फार्म डिजाइन और प्रबंधन की प्रणाली अभिप्रेत है;

(झ) "जैव खेती उत्पाद" से जैव कृषि से प्राप्त उपज अभिप्रेत है;

(ञ) "जैव खाद्य" से जैव उत्पादन के विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार उत्पादित खाद्य उत्पाद अभिप्रेत है;

(ट) 'भारत के लिए प्रत्याभूति प्रणाली" से ऐसे तृतीय पक्ष प्रमाणन के ढाँचे से प्रथक जो उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अन्य पणधारियो की भागीदारी पर बल देता है बाहर कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित जैव उत्पादन के लिए गुणता आश्वासन पहल अभिप्रेत है;

(2) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के , जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों या विनियमों में परिभाषित है, वाही अर्थ होगे जो उस अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों, क्रमशः, में हैं।

अध्याय 2

जैव खाद्य लेबलिंग और प्रमाणन

3. कोई व्यक्ति किसी ऐसे जैव खाद्य का निर्माण, पैकिंग, विक्रय, विक्रय के लिए प्रस्ताव, विपणन या अन्यथा वितरण या आयात नहीं करेगा, जो इन विनियमों में निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता।

4. ''जैव खाद्य'' के रूप में बिक्री के लिए प्रस्तावित या समर्थित खाद्य निम्नलिखित में से किसी एक प्रणाली के सभी लागू उपबंधों का अनुपालन करेगे, अर्थात्:-

(i) राष्ट्रीय जैव उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी);

(ii) भारत के लिए प्रत्याभूति प्रणाली' (पी.जी.एस-इंडिया);

(iii) खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अन्य कोई प्रणाली या मानक।

5. मूल उत्पादक या उत्पादक संगठन द्वारा अंत्य उपभोक्ता को सीधे बिक्री के लिए विपणन हेतु जैव खाद्य को अनुपालन के प्रमाणन की आवश्यकता से छूट है और यह छूट प्रसंस्कृत जैव खाद्य उत्पादों पर लागू नहीं है।

6. लेबलिंग पर उत्पाद की जैवीय स्थिति के बारे में पूरी और सही-सही जानकारी होगी । ऐसे उत्पाद पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के 'प्रतीक' के अतिरिक्त विनियम 4 में उल्लिखित प्रणालियों में से किसी एक प्रणाली का गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन या उसकी मुहर होगी।

7. सभी जैव खाद्य विनियम 4 में उल्लिखित प्रणालियों में से लागू किसी एक प्रणाली की लेबलिंग अपेक्षाओं के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजबंदी और लेबलिंग) विनियम, 2011 में विनिर्दिष्ट पैकेजबंदी और लेबलिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

8. उत्पाद की खोज विनियम 4 में उल्लिखित प्रणालियों के अधीन लागू उत्पादक स्तर तक होगी और खाद्य उत्पाद की जैविक पूर्णता को बनाए रखने के लिए उत्पाद में खाद्य प्राधिकरण द्वारा विहित कोई अन्य अपेक्षा सम्मिलित होगी।

9. सभी जैव खाद्य इन विनियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पायद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, अविष तथा अवशिष्ट) विनयम, 2011, अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों यथा लागू उपबंधों का अनुपालन करेंगे।

10. जैव खाद्य के सभी विक्रेता या तो अकेले, या अपने खुदरा कारोबार के अंग रूप में, ऐसे खाद्य को पारंपरिक खाद्य के प्रदर्शन से स्पष्टत: अलग रीती से प्रदर्शित करेंगे।

11. इन विनियमों के उपबंधों का अपालन अधिनियम के अधीन दंडात्मक उपबंध आकर्षित करेंगे और झूठे, भ्रामक या कपटपूर्ण दावे के लिए दायी होंगे।

अध्याय 3

आयात और विनिमय

12. राष्ट्रीय जैव उत्पादन कार्यक्रम और संबंधित निर्यातक देशों के जैव मानकों की समतुल्यता के आधार पर हुए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों के अधीन जैव खाद्यों के भारत में आयात के लिए पुन: प्रमाणन अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन के अध्यधीन अपेक्षित नहीं होगा।

13. विनियम 12 के अनुसार, सभी जैविक खाद्य परेषनो के साथ समतुल्य करार के निबंधनो के अंतर्गत आने वाले प्रत्यायित प्रमाणन निकाय द्वारा संव्यवहार प्रमाणपत्र संलग्न होगा।

अध्याय 4

साधारण

14. खाद्य प्राधिकरण इन विनियमों के कार्यान्वयन और देश में प्रामाणिक जैव खाद्य के संवर्धन के लिए कोई उपयुक्त संस्थागत प्रणाली स्थापित कर सकेगा।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./111/17]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

Notification

New Delhi, the 19th June, 2017.

F. No. CPB/03/Standards/FSSAI/2016.—The following draft regulations, which the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92 read with sub-section (3) of section 22 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing this notification are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002 or send it to the e-mail address of the Food Authority at regulation@fssai.gov.in ;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period specified above shall be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

CHAPTER I

GENERAL

1. Short title and commencement- (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Organic Foods) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006);

(b) "Accreditation Body" means any agency recognised as such by the Food Authority or recognised under the National Programme for Organic Production for accreditation of certification bodies;

(c) "Accredited Certification Body" means an organisation duly accredited by an Accreditation body for certification of organic products and for granting the right to use the certification mark to the food business operators on behalf of the Accreditation Body;

(d) "Claim" means any representation which states, suggests or implies that a food has particular qualities relating to its origin, nutritional properties, nature, processing and composition;

(e) "Food Authority" means the Food Safety and Standards Authority of India established under section 4 of the Food Safety and Standards Act, 2006;

(f) "National Programme for Organic Production" means a programme of the Government of India which provides an institutional mechanism for implementation of the National Standards for Organic Production with a third-party certification control system as notified by the Director General of Foreign Trade under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992;

(g) "Standards for Organic Production" means any standards recognised by the Food Authority or the National Standards for Organic Production or Participatory Guarantee System for India to be followed in cultivation or harvest or production or storage or processing or trading of organic food products and Inputs;

(h) "Organic agriculture" means a system of farm design and management to create an eco system of agriculture production without the use of synthetic external inputs such as chemicals, fertilizers, pesticides and synthetic hormones or Genetically Modified Organisms;

(i) "Organic farm produce" means the produce obtained from organic agriculture;

(j) "Organic food" means food products that have been produced in accordance with specified standards for organic production;

(k) "Participatory Guarantee System for India" means a quality assurance initiative for organic production operated by the Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare outside the framework of third party certification which emphasizes the the participation of producers, consumers and other stakeholder.

(2) All the other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, or rules or regulations made thereunder shall have the meanings assigned to the same in the Act, rules or regulations respectively.

CHAPTER II

Organic Food Labelling and Certification

3. No person shall manufacture, pack, sell, offer for sale, market or otherwise distribute or import any organic foods unless they comply with the requirements laid down under these regulations.

4. Any food offered or promoted for sale as 'organic food' shall comply with all the applicable provisions of one of the following, namely:-

(I) National Programme for Organic Production (NPOP);
(II) Participatory Guarantee System for India (PGS-India);
(III) Any other system or standards as may be notified by the Food Authority from time to time.

5. The Organic food that is marketed through direct sales by the original producer or producer organisation to the end consumer is exempt from the need of verification of compliance and this exemption does not apply to processed organic food products.

6. Labelling shall convey full and accurate information on the organic status of the product. Such product shall carry a certification or quality assurance mark of one of the systems mentioned in regulation 4 in addition to the Food Safety and Standard Authority of India logo.

7. All organic foods shall comply with the packaging and labelling requirements specified under the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 in addition to the labelling requirements under one of the applicable system mentioned in regulation 4.

8. Traceability shall be established upto the producer level as applicable under the systems mentioned in regulation 4 and it shall include any other requirements prescribed by the Food Authority to maintain the organic integrity of the food product.

9. Without prejudice to the provisions of these regulations, all organic food shall comply with the relevant provisions, as applicable, under the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011, the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, under the Act and the rules and regulations made thereunder.

10. Any seller of organic food either exclusively or as part of their retail merchandise shall display such food in a manner distinguishable from the display of conventional food.

11. Non- compliance of the provisions of these regulations shall attract penal provisions under the Act, and be liable for action as a false, misleading or deceptive claim.

CHAPTER III

Imports and Reciprocity

12. Organic food imports under bilateral or multilateral agreements on the basis of equivalence of standards between National Programme for Organic Production and the organic standards of the respective exporting countries shall not be required to be re-certified on import to India subject to their compliance with the provision of the Act and the rules and regulation made thereunder.

13. All organic food consignments as per regulation 12 shall be accompanied by a transaction certificate issued by an Accredited Certification Body covered under the terms of the equivalence agreement.

CHAPTER IV

General

13. The Food Authority may establish appropriate institutional mechanism to implement these regulations and promote authentic organic food in the country.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./111/17]

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.06.21 19:43:18 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.